

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**मांग संख्या 63**

**विधि और न्याय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	254.74	1138.90	1393.64	280.00	392.17	672.17	280.00	662.25	942.25	1000.00	417.28	1417.28	
पूँजी	...	0.08	0.08	...	15.02	15.02	...	1.75	1.75	...	15.02	15.02	
जोड़	<b>254.74</b>	<b>1138.98</b>	<b>1393.72</b>	<b>280.00</b>	<b>407.19</b>	<b>687.19</b>	<b>280.00</b>	<b>664.00</b>	<b>944.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>432.30</b>	<b>1432.30</b>	
<b>1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं</b>													
1.01 विधि कार्य विभाग	2052	...	29.83	29.83	...	25.48	25.48	...	30.78	30.78	...	43.05	43.05
1.02 विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफई)	2052	...	0.83	0.83	...	0.62	0.62	...	1.09	1.09	...	1.17	1.17
1.03 विधायी विभाग	2052	...	11.42	11.42	...	9.71	9.71	...	13.16	13.16	...	13.20	13.20
1.04 न्याय विभाग	2052	...	1.74	1.74	...	1.93	1.93	...	2.65	2.65	...	9.17	9.17
1.05 अन्य	2052	...	16.69	16.69	...	22.06	22.06	...	24.30	24.30	...	31.29	31.29
जोड़- सचिवालय - सामान्य सेवाएं	...	...	60.51	60.51	...	59.80	59.80	...	71.98	71.98	...	97.88	97.88
<b>2. राज्य चुनावों के अंग</b>													
2.01 चुनाव	2015	...	808.25	808.25	...	78.86	78.86	...	68.86	68.86	...	84.50	84.50
2.02 सामान्य चुनावी खर्च	2015	...	99.57	99.57	...	62.83	62.83	...	177.83	177.83	...	83.29	83.29
2.03 मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना	2015	...	14.39	14.39	...	10.00	10.00	...	160.00	160.00	...	15.51	15.51
जोड़- राज्य चुनावों के अंग	...	...	922.21	922.21	...	151.69	151.69	...	406.69	406.69	...	183.30	183.30
<b>3. राजकोपीय सेवाएं</b>													
3.01 आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण	2020	...	49.07	49.07	...	41.51	41.51	...	44.13	44.13	...	44.98	44.98
3.02 राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण	2020	...	...	...	...	0.05	0.05	...	...	...	...	0.05	0.05
जोड़- राजकोपीय सेवाएं	...	...	49.07	49.07	...	41.56	41.56	...	44.13	44.13	...	45.03	45.03
<b>4. न्याय प्रशासन</b>													
4.01 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी	2014	...	9.70	9.70	...	13.00	13.00	...	9.72	9.72	...	10.74	10.74
4.02 जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	2014	62.36	...	62.36	108.00	...	108.00	108.00	...	108.00	267.00	...	267.00
4.03 विशेष न्यायालय	3601	...	1.00	1.00	...	2.00	2.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
4.04 फास्ट ट्रेक न्यायालय	2014	...	56.13	56.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	...	...	...	...	75.00	75.00	...	74.80	74.80	...	...	...

<http://indiabudget.nic.in>

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
जोड़	...	56.13	56.13	...	75.00	75.00	...	74.80	74.80	...	...	...	
4.05 न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधा हेतु विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	2014	...	...	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00	
4.06 अन्य व्यय	2014	...	32.34	...	41.79	41.79	...	40.28	40.28	...	66.31	66.31	
4.07 भारत में न्याय तक पहुंच का सुदृढीकरण													
4.07.01 सामान्य घटक	2014	2.19	...	2.19	0.57	...	0.57	0.57	...	0.57	...	0.57	
4.07.02 ईपीए घटक	2014	...	...	...	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	...	7.00	
जोड़- भारत में न्याय तक पहुंच का सुदृढीकरण		2.19	...	2.19	7.57	...	7.57	7.57	...	7.57	...	7.57	
4.08 न्याय प्रशासन परियोजना	2014	14.80	...	14.80	...	...	...	...	...	...	...	...	
4.09 न्यायिक सुधारों तथा निर्धारण प्रास्थिति का अध्ययन	2014	1.02	...	1.02	2.43	...	2.43	2.43	...	2.43	2.53	2.53	
4.10 अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र	2014	...	...	...	...	0.01	0.01	...	2.26	2.26	...	0.01	
4.11 ग्राम न्यायालयों की स्थापना और प्रचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता	2014	13.47	...	13.47	39.00	...	39.00	39.00	...	39.00	145.00	145.00	
जोड़- न्याय प्रशासन		93.84	99.17	193.01	157.00	131.80	288.80	157.00	132.06	289.06	447.10	82.06	529.16
5. अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
5.01 न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं	3601	155.90	...	155.90	95.00	...	95.00	95.00	...	95.00	427.90	...	427.90
5.02 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता-अनुदान	3602	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00
5.03 अन्य कार्यक्रम	2070	...	7.94	7.94	...	7.32	7.32	...	7.39	7.39	...	9.01	9.01
5.04 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070	...	0.08	0.08	...	15.02	15.02	...	1.75	1.75	...	15.02	15.02
जोड़- अन्य प्रशासनिक सेवाएं		160.90	8.02	168.92	95.00	22.34	117.34	95.00	9.14	104.14	452.90	24.03	476.93
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00	100.00	...	100.00
	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		...	...	...	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00	100.00	...	100.00
<b>कुल जोड़</b>		<b>254.74</b>	<b>1138.98</b>	<b>1393.72</b>	<b>280.00</b>	<b>407.19</b>	<b>687.19</b>	<b>280.00</b>	<b>664.00</b>	<b>944.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>432.30</b>	<b>1432.30</b>
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	

ग. योजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
		आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	
1. न्याय प्रशासन	32014	254.74	...	254.74	252.00	...	252.00	252.00	...	252.00	900.00	...	900.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00	100.00	...	100.00
<b>जोड़</b>		<b>254.74</b>	...	<b>254.74</b>	<b>280.00</b>	...	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	...	<b>280.00</b>	<b>1000.00</b>	...	<b>1000.00</b>

1.01-1.04. इसमें विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के सचिवालय व्यय के साथ-साथ विदेशी मुद्रा विनिमय अपीलीय न्यायाधिकरण के व्यय के लिए प्रावधान किए गए हैं।

1.05. यह प्रावधान, राजभाषा खण्ड, जो केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और उनके मुद्रण के लिए उत्तरदायी है तथा संगठित मुकदमा अभिकरण के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है जो केन्द्रीय अभिकरण की योजना में सम्मिलित केन्द्रीय और राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

2.01. यह प्रावधान लोक सभा के आम चुनाव की बकाया देनदारी को वहन करने के लिए है।

2.02. यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को साधारण चुनाव व्यय से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए है। इसमें मतदाता सूचियों आदि की तैयारी और मुद्रण की लागत भी शामिल है।

2.03. यह प्रावधान मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने पर हुए व्यय के सम्बन्ध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए है।

3.01. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना मुख्य आयकर आयुक्तों, आयकर महानिदेशकों, आयकर आयुक्तों, आयकर आयुक्तों (अपील) और आयकर उपायुक्तों (अपील) के निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन की गई है।

3.02. राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना, प्रत्यक्ष करों की वसूली, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन संबंधी विवादों के न्याय-निर्णयन तथा सेवाओं पर कर वसूली एवं माल पर सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों और ऐसे कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ माल की कीमत संबंधी विवादों के न्याय-निर्णयन हेतु की गई है।

4.01. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी 17 अगस्त, 1993 से एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित की गई थी। यह प्रावधान अकादमी के आवर्ती व्यय के लिए है।

4.02. यह प्रावधान जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण पर व्यय हेतु किया गया है।

4.03. यह प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिवार -न्यायालयों पर होने वाले व्यय के लिए किया गया है।  
<http://indiabudget.nic.in>

4.04. पहले यह प्रावधान फास्ट ट्रैक न्यायालयों के आवर्ती तथा गैर - आवर्ती व्यय को वहन करने के लिए किया गया था। 31 मार्च, 2011 के बाद फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए केन्द्रीय निधियां नहीं होंगी।

4.05. यह प्रावधान विधान मण्डल रहित संघ शासित क्षेत्रों की सहायता के लिए न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए है।

4.06. यह प्रावधान विधि अधिकारियों, विधि सलाहकारों तथा परामर्शियों के लिए तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा गरीबों के लिए विधि सहायता उपलब्ध करवाने के लिए है।

4.07.1-2. यह प्रावधान मुख्य रूप से न्याय के लिए पहुंच सुगम करने-भारत (साजी) के बारे में न्याय विभाग द्वारा यू एन डी पी की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

4.08. यह उपबंध मुख्य रूप से न्याय प्रशासन के लिए न्याय विभाग द्वारा ए.डी.बी. की परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित है।

4.09. यह उपबंध, न्यायिक सुधारों के बारे में व्यवस्थित अध्ययन को अपनाने हेतु है।

4.10. यह प्रावधान विवादों के शीघ्र समाधान और न्यायालय में लम्बित मुकदमों की संख्या में कमी करने के प्रयोजन से वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों को प्रोत्साहित, संगठित एवं प्रचारित करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (आई सी ए डी आर) के लिए नई दिल्ली में एक कन्वेंशन सेन्टर, बिजनेस सेन्टर और फ्यूचर ब्लॉक के निर्माण हेतु सहायता अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए है।

4.11. यह प्रावधान ग्राम न्यायालयों की स्थापना तथा संचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

5.01-5.02. यह प्रावधान एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जो न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए और विधान मण्डल वाले संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान/सहायता प्रदान करने के लिए न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए है।

5.03. यह प्रावधान विधि आयोग, अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ और विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा कानूनी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने के लिए किया गया है।

5.04. यह प्रावधान विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों तथा राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के लिए भूमि अधिग्रहण तथा भवनों के निर्माण के लिए है।

6. यह प्रावधान उत्तर - पूर्वी क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।